vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. RAJHIN/2019/77486
मूल्यः 25 रूपये

तीर निशाने पर

विशिखा

वर्ष: 07 अंक: 6 जून 2025 पृष्ठ:32

राजस्थान संस्करण

_vishikhamedia/ vishikhamedia/ vishikhamedia/
vishikhamedia vishikhamedia.in

ऑपरेशन सिंदूर

भारत की ताकत और विपक्ष की राजनीति का नया द्वंद

विशिखा

विशिखा न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

विराट कोहली का टेस्ट संन्यास

हर रन था जुनून, हर पारी एक जंग

टेस्ट क्रिकेट, जिसे क्रिकेट का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है, वहां कोहली ने खुद को एक योद्धा की तरह साबित किया। विराट कोहली जुनून, अनुशासन और आक्रामकता के प्रतीक भर नहीं थे। उनकी विदाई सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं है, यह एक भावना का अंत है।

10 | हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर विशेष
पत्रकारिता के पतन के बीच उम्मीद की किरण भी

12 | उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांडः तीनों दोषियों को उम्रकैद

14 | यूपी की राजनीति में गिरती भाषा और बढ़ती टेल नीति

16 | पता नहीं कब तक रहेंगी सरहदों की दूरियां...
ज्योति की डायरी से पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा

18 | पूर्व सीजेआई चन्द्रचूड़ के गले की फांस बना तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देना

20 | सेना के साथ खड़ा भारत, सत्ता के लिए लड़ता पाकिस्तान

24 | कांग्रेस अपने इस नेता को क्यों शक की नजर से देखती है?

26 | कैंसर के इलाज में क्यों झड़ते हैं बाल? वैज्ञानिकों ने ढूंढा समाधान

27 | मधुमेह के खतरे को कम करने के लिए स्कूलों में लगेंगे 'शुगर बोर्ड'

28 | भारत-पाक युद्ध के बाद ट्रंप की रणनीति में बदलाव दोस्ती या तकरार?

30 | राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित करणी माता मंदिर
आस्था, अद्भुत परंपराएं और चूहों का अद्वितीय संसार

विशिखा
तीर निशाने पर
अंक: 6 वर्ष:07, जून 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
तीन निशाने पर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** 191/56 (जानकी देवी स्कूल के पास) सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर- 302033 राजस्थान के लिए प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
*पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

अ०परेशन सिंदूर.... जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अ०परेशन सिंदूर के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया, विपक्षी दलों ने इस बार न केवल सरकार का समर्थन किया बल्कि सेना के साहस और कार्रवाई की भी खुलकर सराहना की।

'अ०परेशन सिंदूर' की शुरुआत एक गुप्त अभियान के तौर पर हुई थी, जिसका उद्देश्य कथित रूप से कश्मीर घाटी में आतंक के नेटवर्क को समाप्त कर पाकिस्तान समर्थित तत्वों को निष्क्रिय करना था। इस अ०परेशन का नाम 'सिंदूर' रखने के पीछे का कारण भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक था।

अ०परेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य कार्रवाई बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त प्रतीक बन गया है। इस अ०परेशन ने न केवल सीमाओं पर बैठे दुश्मनों को सीधा संदेश दिया, बल्कि विश्व में भारत की स्थिति को मजबूत किया है।

ये कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह सिंदूर का सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह भारतीय राजनीति की भाषा के स्तर को गिराता है। इसी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी मौत का सौदागर कहा था। अब सिंदूर का सौदागर कहकर बीजेपी को यह बताया जा रहा है कि वह देशभक्ति को बेचना चाहती है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक के समय कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने शुरुआत में सरकार का समर्थन किया था, लेकिन चुनावों के आते ही उन्होंने मोर्चा बदल लिया था।

उधर दूसरी ओर अ०परेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति डगमगाई हुई है, पाकिस्तान की सियासत भी बुरी तरह बिखर गई है। इस वक्त जब उनको एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए, इसकी बजाय पाकिस्तानी नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त हैं।

कुल मिलाकर अ०परेशन सिंदूर के जरिये देश ने विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे विश्व को अपनी ताकत का अहसास करा दिया है, इससे अब कोई भी आतंकी देश भारत की तरफ आँख उठाने से पहले कई बार सोचेगा...

शेष फिर....

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ काटना मना

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2015 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के भीतर बिना अनुमति के पेड़ नहीं काटे जा सकते। अगर पेड़ों की संख्या 50 से कम भी हो, तब भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ताजमहल से 5 किमी से बाहर लेकिन टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पेड़ काटने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अंतर्गत आने वाले प्रभागीय वन अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत कार्य करेंगे।

2015 का आदेश रहेगा लागू

पीठ ने कहा कि ताजमहल के 5 किलोमीटर के भीतर पेड़ों की कटाई के संबंध में 8 मई 2015 का मूल आदेश लागू रहेगा। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, भले ही कटने वाले पेड़ों की संख्या 50 से कम हो। कोर्ट पहले समिति से सिफारिश मांगेगी और फिर कटाई पर विचार होगा।

यह भी कहा गया कि जब तक पेड़ों को काटना अत्यंत आवश्यक न हो, तब तक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण जैसी शर्तों का पूरा पालन किया जाए।

आपको बता दें 8 मई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) में किसी भी पेड़ की कटाई बिना अदालत की अनुमति के नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य वनों की कटाई रोकना और जैव विविधता की रक्षा करना था। हालांकि, 11 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने संशोधन कर गैर–वन और निजी जमीन पर कटाई के लिए पूर्व अनुमति की अनिवार्यता हटा दी थी।

आगरा के ट्रस्ट की याचिका खारिज

कोर्ट ने एक ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें निजी भूमि पर पेड़ काटने की पूर्व अनुमति की शर्त से छूट की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल ऐसे अपवादों में पेड़ काटने की इजाजत दी जा सकती है, जहाँ पेड़ के गिरने से मानव जीवन को खतरा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने ब्ब से यह रिपोर्ट भी मांगी है कि आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत है या नहीं।

क्या है ताज ट्रेपेजियम जोन

ताज ट्रेपेजियम जोन एक विशेष पर्यावरणीय क्षेत्र है, जो ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए बनाया गया है। यह जोन लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा और राजस्थान का भरतपुर जिला शामिल हैं।

ऑपरेशन सिंदूर

भारत की ताकत और विपक्ष की राजनीति का नया द्वंद

संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर कई बड़े देशों ने भारत के इस साहसी कदम की प्रशंसा की है। लेकिन देश के भीतर एक अजीब सा राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। जिस समय जनता एकजुट होकर सेना के पराक्रम पर गर्व कर रही है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस ऑपरेशन पर सवाल उठाकर खुद को कठघरे में खड़ा कर रही है।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक सशक्त प्रतीक बन चुका है। इस ऑपरेशन ने न केवल सीमाओं पर बैठे दुश्मनों को सीधा संदेश दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति को मजबूत किया है। देशभर में इस ऑपरेशन की सराहना हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर कई बड़े देशों ने भारत के इस साहसी कदम की प्रशंसा की है। लेकिन देश के भीतर एक अजीब सा राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। जिस समय जनता एकजुट होकर सेना के पराक्रम पर गर्व कर रही है, उसी समय प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस ऑपरेशन पर सवाल उठाकर खुद को कठघरे में खड़ा कर रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह सरकार से यह पूछा कि कितने फाइटर प्लेन गिरे, यह सवाल वाजिब होते हुए भी एक गलत समय पर उठाया गया। जब देश युद्ध की स्थिति में होता है, तब जवाबदेही का मतलब समर्थन होता है, न कि सवालों की बौछार। राहुल गांधी का यह बयान कि सच जानना हमारा हक हैष अपने आप में सही है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि सेना के मनोबल को ऐसे समय में ठेस न पहुंचे। एयर मार्शल ए. के. भारती ने साफ कहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और इसमें नुकसान भी होता है, लेकिन क्या हमने अपने लक्ष्य हासिल किए? जवाब है हां। तो जब सेना खुद कह रही है कि उन्होंने मिशन को सफलता से पूरा किया है, तो सवाल पूछने की टाइमिंग पर बहस तो होगी ही।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को 'मुखबिर' कहने का आरोप और भी गंभीर है। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने यह दावा किया कि जयशंकर ने ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी, जिससे

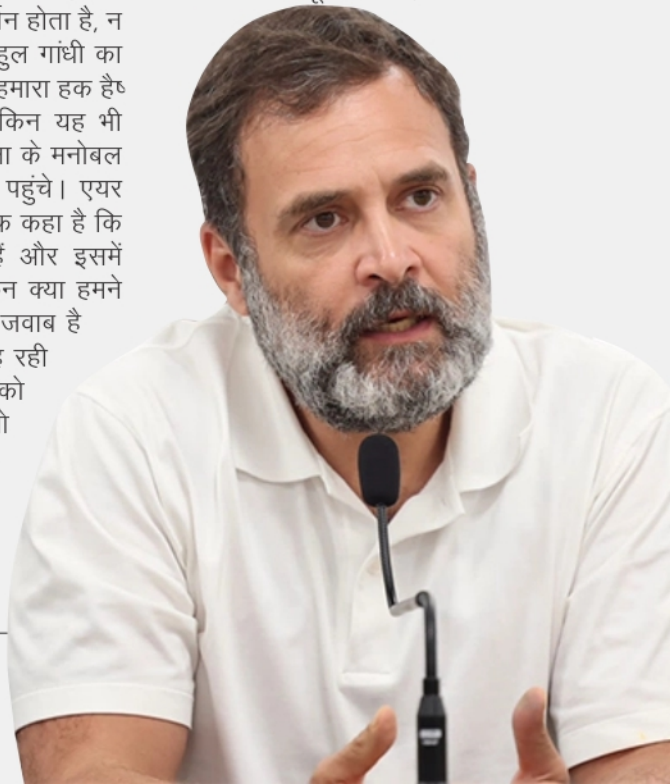

आतंकवादी बच निकले। इस दावे के पीछे जयशंकर का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट किया कि हमला आतंकवादियों पर होगा, न कि पाकिस्तानी सेना पर। यह बयान युद्ध को टालने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन जुटाने की कूटनीतिक कोशिश थी, लेकिन विपक्ष ने इसे एक तरह से देशद्रोह करार दे दिया। क्या यह उचित है कि एक वैश्विक कूटनीति को इस तरह राजनीति का विषय बना दिया जाए?

राहुल गांधी की यह बात कि अगर पाकिस्तान को पहले से जानकारी थी तो मसूद अजहर के घर के दस से ज्यादा लोग मारे कैसे गए? अपने आप में कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के लिए काफी है। यह साफ संकेत है कि भारत ने एक तरफ आतंकियों को मार गिराया, वहीं पाकिस्तान की सेना से सीधी भिड़ंत से बचकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। इस रणनीति को कोई समझे या न समझे, पर इसे मुखबिरी कहना न केवल बचकाना है बल्कि खतरनाक भी।

इस पूरे ऑपरेशन पर जो राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है, वह अब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी इस ऑपरेशन को राष्ट्रवादी अभियान के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी द्वारा राष्ट्रवाद के नाम पर 'राजनीतिक सौदा'

भारत में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। लोकतंत्र में यह विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए, गलतियों की ओर ध्यान दिलाए। लेकिन जब देश युद्ध की स्थिति में होता है, तब आलोचना और समर्थन के बीच की रेखा बहुत महीन हो जाती है।

बता रही है। कांग्रेस द्वारा 'सिंदूर का सौदागर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह बताता है कि राजनीति का स्तर किस दिशा में जा रहा है। क्या यह वही पार्टी है जिसने सर्वदलीय बैठक में सरकार को पूरा समर्थन देने का वादा किया था? 8 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा था कि इस संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की उस प्रतिबद्धता का क्या हुआ?

दरअसल, कांग्रेस की रणनीति अब जय हिंद सभाओं के जरिए बीजेपी पर हमला करने की है। 20 से 30 मई के बीच देशभर में कांग्रेस ऐसी सभाएं आयोजित कर रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन जनता यह सवाल भी पूछ रही है कि क्या यह सभाएं सेना के मनोबल के खिलाफ नहीं जा रही हैं? क्या इन सभाओं का मकसद राष्ट्रवाद की भावना को चोट पहुंचाना नहीं है?

भारत में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। लोकतंत्र में यह विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए, गलतियों की ओर ध्यान दिलाए। लेकिन जब देश युद्ध की स्थिति में होता है, तब आलोचना और समर्थन के बीच की रेखा बहुत महीन हो जाती है। यही वजह है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक के समय कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरंभिक रूप से सरकार का समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही चुनावी राजनीति आई, उन्होंने मोर्चा बदल लिया। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है।

राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों में यह भी शामिल था कि भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह सवाल उचित हो सकता है, लेकिन इस सवाल का समय और मंच गलत है। युद्ध के समय इस तरह के सवालों से दुश्मन देश को ही लाभ होता है। पाकिस्तान की संसद में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया और इसे कायरता करार दिया। जब पाकिस्तान की सरकार भारत को कायर बता रही है और भारत का विपक्ष कह रहा है कि भारत ने हमला बताकर किया, तो क्या इससे भारत की छवि को नुकसान नहीं होता?

सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है जनता का समर्थन। अगर देश की जनता एकजुट होकर अपने जवानों के पीछे खड़ी हो तो सेना का मनोबल ऊँचा रहता है। लेकिन जब देश के भीतर से ही विपक्ष इस तरह के सवाल उठाकर सेना की नीतियों पर संदेह करता है, तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह आलोचना है या राजनीतिक हथियार?

कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह सिंदूर का सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, वह भारतीय राजनीति की भाषा के स्तर को गिराता है। यह वही कांग्रेस है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी मौत का सौदागर कहा था। अब सिंदूर का सौदागर कहकर बीजेपी को यह जताया

चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी राष्ट्रवाद को बेच रही है, तो उसे खरीद कौन रहा है? क्या जनता इतनी भोली है कि वह राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ भूल जाती है?

आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों के जरिए भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले रहा है, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह इन प्रयासों का समर्थन करे? आलोचना जरूर होनी चाहिए लेकिन समय देखकर, मंच देखकर और शब्दों को मापकर। भारत का आम नागरिक यह पूछ रहा है कि जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो, तब विपक्ष क्यों एकजुट नहीं हो सकता? क्या राजनीति इतनी जरूरी हो गई है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी ऊपर हो जाए?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सवाल पूछने की आजादी सबको है। लेकिन सवाल वही पूछे जाते हैं जो जरूरी हों, और समय वही चुना जाता है जो उचित हो। कांग्रेस की बदली हुई रणनीति और तीखे आरोप न केवल उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरे की घंटी हैं। जनता सब देख रही है, आने वाले चुनावों

चीनी खिलौने मिसाइल, पाक फुस इंडियन आर्मी ने खिलौनों की तरह तोड़े

कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की भी पेशानी पर बल ला दिया है। दरअसल, भारतीय सेना पाकिस्तान को बुरी तरह से सबक सिखा रही है तो चीन की चिंता इस बात को लेकर है कि इस युद्ध में चीनी हथियारों की पोल खुलती जा रही है, पाकिस्तान द्वारा दागी जा रही चीनी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से एक के बाद एक धराशायी करती जा रही है। सैकड़ों चीनी मिसाइलों को इंडियन आर्मी हवा में ही मार गिरा चुकी है। संभवता इसी के चलते पाकिस्तान की बौखलाहट के साथ ड्रैगन यानी चीन की चिंता बढ़ी हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान से शांति की अपील करते हुए ज्ञान दिया कि बात आगे बढ़ी तो किसी के हित में नहीं होगा। ऐसा करते हुए उसने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर चुप्पी साधे रखी।

बहरहाल, चीन ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के मेज पर वापस आने की सलाह देते हुए कहा कि वह मध्यस्थता करने का इच्छुक है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा, हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि शांति और स्थिरता के हित में संयम और शांति बरतें और शांतिपूर्वक साधनों से राजनीतिक सुलह के रास्ते पर वापस

आएं। किसी भी ऐसे ऐक्शन से बचें जो तनाव को और ज्यादा बढ़ाए। यह भारत और पाकिस्तान दोनों के हित में होगा और क्षेत्र तकी शांति स्थिरता के लिए आवश्यक है। वैश्विक समुदाय भी इसी की उम्मीद कर रहा है। इसे खत्म कराने के लिए चीन भूमिका निभाने का इच्छुक है।

गौरतलब है कि चीन अपने फायदों के लिए पाकिस्तान को सबसे करीबी दोस्त होने के भ्रमजाल में फंसाए हुए है। चीन ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत के रुख और सैन्य ताकत को देखते हुए चीन को अब अपने प्रॉजेक्ट्स पर भी असर होने का अंदेशा होने लगा है। आतंकवाद को लेकर हमेशा चीन का बचाव करता रहा ड्रैगन अब उसकी पिटाई देख झगड़ा रोकने की इच्छा जाहिर कर रहा है।

उधर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत में हमले की नाकाम कोशिशें की हैं तो दूसरी जवाबी कार्रवाई में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान के चार एयरबेस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा स्थिति करीब से निगाह रखी जा रही है। चीन ने टकराव बढ़ने पर अपनी चिंता जाहिर की है।

वायुसेना ने गढ़ा नया इतिहास
गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार रात में हुई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग

भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित जलालाबाद क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत का अद्भुत प्रदर्शन किया।

दिन में जहां विभिन्न विमानों ने एक्सप्रेसवे पर उड़ान भरकर रोमांच पैदा किया, वहीं रात में पहली बार लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। यह देश में पहला मौका है जब किसी एक्सप्रेसवे पर रात के समय फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की हो।

पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच वायुसेना के इस अभ्यास ने रणनीतिक रूप से भारत की तैयारियों का प्रदर्शन किया। राफेल, सुखोई–30, मिग–29, जगुआर और सुपर हरक्यूलिस जैसे विमानों ने जलालाबाद के पीरू गांव के पास बनी विशेष हवाई पट्टी पर टचडाउन कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत भी उन गिने–चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो एक्सप्रेसवे को रनवे के रूप में रात में भी इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं।

एयर शो का विवरण

- पूर्वाह्न 11:30 बजे शुरू होने वाला एयर शो मौसम के कारण करीब एक घंटे देरी से शुरू हुआ।
- दोपहर 12:40 बजे एएन–32 विमान की लैंडिंग के साथ शो की शुरुआत हुई, जो दोपहर 2:30 बजे तक चला।
- सी–130 जे हरक्यूलिस, जगुआर, मिग–29, राफेल और सुखोई–30 जैसे विमानों ने क्रमशः हवाई पट्टी को स्पर्श किया और उड़ान भरी।
- एमआई–17 वी–5 हेलिकॉप्टर से सैनिकों ने रस्सियों के सहारे उतरकर आपात स्थिति के लिए अभ्यास किया।
- शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कटरा–जलालाबाद हाईवे को बंद कर दिया गया, ताकि रात 9 बजे शुरू होने वाली नाइट लैंडिंग बिना व्यवधान संपन्न हो सके।

सुखोई और राफेल का रोमांचक प्रदर्शन:

सुखोई–30 ने छह बार हवाई पट्टी को छूते हुए कम ऊंचाई पर रोमांचक कलाबाजियाँ दिखाईं। राफेल, मिग–29, जगुआर और सुपर हरक्यूलिस ने भी शानदार प्रदर्शन किया। यह सब देखकर उपस्थित ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

रणनीतिक उद्देश्य

इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध या आपातकाल की स्थिति में पारंपरिक एयरबेस के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में एक्सप्रेसवे का विकल्प के रूप में प्रयोग करना है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 3.5 किमी लंबी पट्टी को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो युद्ध और आपदा प्रबंधन दोनों में उपयोगी साबित होगी।

ग्रामीणों का उत्साह और प्रशासन की तैयारी:

एयर शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग बाइक, कार और ट्रैक्टरों से शो देखने पहुंचे। ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला, विशेषकर रात की लैंडिंग को देखने के लिए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे, लगभग एक दर्जन गांवों में पुलिस बल तैनात किया गया था। तेज आंधी के बावजूद लोग डटे रहे और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने।

एयर शो का शनिवार को आयोजन

शुक्रवार को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए एयर शो और नाइट लैंडिंग के बाद वायुसेना ने शो को रद्द कर दिया है। पहले यह शो दो दिन प्रस्तावित था।

नेताओं की उपस्थिति:

कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद रहे, जिन्होंने बैकग्राउंड में उड़ते लड़ाकू विमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर विशेष

पत्रकारिता के पतन के बीच उम्मीद की किरण भी

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है समाज को सही, निष्पक्ष और सत्य सूचना देना, ताकि नागरिक अपनी राय बना सकें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। विशेष रूप से हिन्दी पत्रकारिता ने आजादी की लड़ाई से लेकर सामाजिक आंदोलनों तक में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन वर्तमान समय में हिन्दी पत्रकारिता जिस रास्ते पर चल रही है, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पत्रकारिता अब नैतिकता से दूर हो गई है? क्या वह अब जनसेवा से अधिक व्यवसाय बन चुकी है? इस विश्लेषण में हम हिन्दी पत्रकारिता के नैतिक पतन के कारणों और उसके सामाजिक प्रभावों की गहराई से समीक्षा करेंगे।

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 1826 में 'उदन्त मार्तण्ड' नामक समाचार पत्र से हुई थी। उस दौर में पत्रकारिता एक मिशन थी, समाज सुधार, स्वतंत्रता संग्राम और जागरूकता फैलाने का माध्यम। बालमुकुन्द गुप्त, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकारों ने कलम को हथियार बनाया और जनता की आवाज बने। उनका उद्देश्य सत्य की खोज और समाज के प्रति उत्तरदायित्व था। लेकिन आज हिन्दी पत्रकारिता जिस दिशा में जा रही है, वह चिंताजनक है। अब पत्रकारिता का मकसद खबर देना नहीं, खबर 'बेचना' हो गया है। हिन्दी पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों की गिरावट के कारणों को बिन्दुवार समझना जरूरी है।

व्यवसायीकरण और कॉर्पोरेट दबाव

मीडिया हाउस अब स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रह गए हैं। अधिकांश बड़े हिन्दी अखबार और न्यूज चौनल बड़े कारपोरेट घरानों के अधीन हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य मुनाफा कमाना है, न कि सामाजिक जागरूकता फैलाना। जब संपादकीय नीति विज्ञापनदाताओं और राजनीतिक समर्थकों के इशारे पर तय होती है, तो निष्पक्षता और ईमानदारी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है।

पेड न्यूज और खबरों की दलाली

आज "पेड न्यूज" एक गंभीर समस्या बन चुकी है। राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों और अन्य हित समूहों द्वारा पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को पैसे देकर अपने पक्ष में खबरें छपवाना एक आम प्रथा बन गई है। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुँचा है।

टीआरपी और क्लिकबेट की होड़'

टीवी चौनलों पर टीआरपी की होड़ और

डिजिटल मीडिया में क्लिकबेट हेडलाइनों ने पत्रकारिता को सतही बना दिया है। गहराई वाली, शोधपरक खबरों की जगह अब सनसनीखेज, उत्तेजक और भावनात्मक सामग्री परोसने का चलन है। इससे जनता को सच्चाई नहीं, बल्कि भ्रमित करने वाली सूचनाएं मिलती हैं।

पत्रकारों की सामाजिक और पेशेवर असुरक्षा

कई पत्रकार न्यून वेतन पर कार्य करते हैं, उनके पास सुरक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी होती है। ऐसे में जब उन पर दबाव आता है या रिश्वत का प्रलोभन दिया जाता है, तो नैतिकता से समझौता करना आसान हो जाता है। इस असुरक्षा का फायदा बड़े संस्थान और राजनैतिक ताकतें उठाते हैं।

राजनीतिक पक्षधरता

हिन्दी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब खुलकर किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। निष्पक्ष रिपोर्टिंग की बजाय 'नैरेटिव सेट करना' अब पत्रकारों का काम बन गया है। इससे खबरें विचारधारा आधारित प्रचार में बदल जाती हैं। नैतिक मूल्यों की अनदेखी के दुष्परिणाम बहुत भयावह नजर आ रहा है,जिसकी तह में जाया जाये तो निम्न वजह सामने आती हैं।

जनता का विश्वास खोना

जब पत्रकारिता पक्षपातपूर्ण, झूठी या अधूरी खबरें परोसती है, तो आम जनता का भरोसा मीडिया पर से उठने लगता है। इससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है क्योंकि जागरूक नागरिक ही सशक्त लोकतंत्र की नींव होते हैं। नैतिकता के अभाव में मीडिया प्लेटफॉर्म अफवाहों, नफरत और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि धार्मिक या जातीय मुद्दों को जानबूझकर उकसाया गया, जिससे हिंसा और तनाव फैल गया।

वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना

नैतिक रूप से गिरा हुआ मीडिया जनहित के मुद्दों जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण की बजाय टीआरपी लायक मसालों को प्राथमिकता देता है। इससे समाज की मूल समस्याएँ हाशिए पर चली जाती हैं।वहीं जब युवा पत्रकारिता को सिर्फ करियर या फेम के नजरिये से देखते हैं, और जब मीडिया संस्थान उन्हें नैतिकता की जगह कंटेंट मैनेजमेंट सिखाते हैं, तो एक पूरी पीढ़ी पत्रकारिता के असली उद्देश्य से भटक जाती है।

हिन्दी पत्रकारिता में कैसे सुधार लाकर उसको पुरानी विश्वसनीयता को लौटाया जा सकता है, इसकी बात की जाये तो

हिन्दी पत्रकारिता का नैतिक पतन एक गंभीर और बहुस्तरीय समस्या है। यह केवल मीडिया संस्थानों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का प्रश्न है। जब पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य- सत्य की खोज, जनसेवा और सत्ता पर प्रश्न उठाने की प्रवृति से विमुख हो जाती है, तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगता है।

यह कहा जा सकता है कि आम नागरिकों को यह समझाने की जरूरत है कि मीडिया कैसे काम करता है, खबरों की जांच कैसे करें, और कौन–सी सूचनाएं भरोसेमंद हैं। इसके साथ ही एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो हिन्दी पत्रकारिता की स्वायत्त और निष्पक्ष निकाय, मीडिया की नैतिकता की निगरानी करे और उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह बनाए।

इसके साथ ही पत्रकारों को नैतिकता, शोध विधियों और कानूनी अधिकारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। वहीं इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि यदि पाठक, दर्शक और श्रोता सतर्क रहेंगे, झूठी खबरों का विरोध करेंगे, और ईमानदार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करेंगे, तो संस्थानों पर भी दबाव बनेगा।

दरअसल, हिन्दी पत्रकारिता का नैतिक पतन एक गंभीर और बहुस्तरीय समस्या है। यह केवल मीडिया संस्थानों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का प्रश्न है। जब पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य– सत्य की खोज, जनसेवा और सत्ता पर प्रश्न उठाने की प्रवृति से विमुख हो जाती है, तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगता है। हालांकि, निराशा के बीच आशा की किरण भी है।

आज भी कई स्वतंत्र और निष्ठावान पत्रकार सत्य के पक्ष में खड़े हैं। यदि समाज, संस्थाएं और नागरिक मिलकर नैतिक पत्रकारिता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें, तो

उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांडः तीनों दोषियों को उम्रकैद

- अदालत ने कहा–अंकिता नहर में गिरी नहीं, जबरन फेंकी गई थी।
- मैं गरीब हूं, तो क्या खुद को 10,000 में बेच दूं?
- अंकिता की पीड़ा उसकी व्हाट्सएप चैट में उजागर

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत कठोरतम उम्रकैद की सजा सुनाई।

अंकिता भंडारी की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई। रिपोर्ट ने साफ किया कि वह नहर में हादसतन नहीं गिरी थी, बल्कि उसे जबरन धक्का देकर फेंका गया था। 'सडन एस्कलरेशन ऑफ बॉडी' यानी शरीर को झटके में पानी में फेंकने की थ्योरी को बचाव पक्ष ने नकारने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक साक्ष्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ने अदालत को संतुष्ट किया।

क्या था मामला?

अंकिता ऋषिकेश के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, जिसे मुख्य आरोपी पुलकित आर्य संचालित करता था। अभियोजन के मुताबिक, अंकिता पर एक वीआईपी मेहमान को 'विशेष सेवा' देने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया। इसी वजह से उसकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई।

व्हाट्सएप चौट्स में अंकिता का दर्द

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में अंकिता की व्हाट्सएप चौट्स पेश कीं, साफ दिखा कि वह आरोपियों के अनुचित प्रस्तावों और दबाव से मानसिक रूप से परेशान थी। एक चौट में उसने लिखा था, "मैं गरीब हूं, तो क्या खुद को 10,000 में बेच दूं?" यह उसके अंदर चल रहे मानसिक संघर्ष की तीव्रता को दिखाता है।

घटना की रात क्या हुआ था?

18 सितंबर 2022 की शाम को गवाहों ने अंकिता को रोते हुए फोन पर किसी से यह कहते सुना था कृ "प्लीज मुझे यहां से ले जाओ।" सीसीटीवी फुटेज में उसे पुलकित आर्य के साथ स्कूटर पर देखा गया, जबकि बाकी दो आरोपी बाइक पर पीछे थे। उसी रात से वह लापता हो गई और छह दिन बाद उसका शव चीला बैराज की नहर से बरामद हुआ।

कोर्ट में 'लास्ट सीन थ्योरी' पर भरोसा

प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण कोर्ट ने 'लास्ट सीन थ्योरी' को अपनाया और दिल्ली हाईकोर्ट के 2009 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत हों कि वे किसी आरोपी की सीधी संलिप्तता साबित करें, तो गवाहों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती।

मेडिकल और फॉरेंसिक जांच से हुआ खुलासा

पोस्टमार्टम और क्राइम सीन की जांच में यह सामने आया कि नहर की पटरी पर फिसलने के कोई निशान नहीं थे। विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट किया कि अंकिता को एक झटके में पानी में फेंका गया था। उसके शरीर पर भी ऐसे कोई घाव नहीं पाए गए जो फिसलने का संकेत देते।

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

शुरुआती जांच में पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रिजॉर्ट का सीसीटीवी खराब था और कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर भ्रम फैलाया। इसके बावजूद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों की कड़ी ने सच सामने ला दिया।

आरोपियों को सजा

कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 354(क) (यौन उत्पीड़न) और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने माना कि यह हत्या जानबूझकर की गई और इसका मकसद पीड़िता को चुप कराना था।

परिवार की प्रतिक्रिया

जैसे ही अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई, अंकिता की मां सोनी देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, "तीनों हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए थी। हम इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे।" बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें सजा से पूरी तसल्ली नहीं है, लेकिन शायद हमारी बेटी की आत्मा को अब थोड़ी शांति मिल सकेगी।"

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, केंद्र ने चुने प्रमुख सांसद

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की सच्चाई को उजागर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने तय किया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका समेत कई अहम देशों का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी, **AIMIM** के असदुद्दीन ओवैसी, और एनसीपी की सुप्रिया सुले जैसे प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। यह विशेष रिपोर्ट नवनीत मिश्र और शादाब अहमद द्वारा प्रस्तुत की गई है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नया कूटनीतिक अभियान

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान से समर्थन मिलने के बावजूद वह लगातार झूठ फैला रहा है। अब भारत सरकार ने उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत 22 से 30 मई के बीच यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई अहम देशों में अलग–अलग सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी दलों के सांसदों से प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए संपर्क कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी, ।प्डप्ड प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, और एनसीपी की सुप्रिया सुले जैसे नामों को शामिल किया जा रहा है।

कांग्रेस ने दिए अपने प्रतिनिधियों के नाम

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जानकारी दी कि किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से संपर्क किया और प्रतिनिधिमंडल के लिए नाम मांगे। इसके तहत कांग्रेस ने निम्नलिखित नाम प्रस्तावित किए:

- आनंद शर्मा
- गौरव गोगोई
- डॉ. सैयद नसीर हुसैन
- राजा बरार

दुनिया को बताएगा भारतः क्यों जरूरी था 'ऑपरेशन सिंदूर'

भारत सरकार ने यह तय किया है कि प्रतिनिधिमंडल अलग–अलग देशों के नेताओं और थिंक टैंक्स से मिलकर बताएगा कि आतंकवाद के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' क्यों जरूरी था। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान ने आतंकी आकाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते भारत को आत्मरक्षा में सीमापार जाकर कार्रवाई करनी पड़ी। भारत की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार में की गई थी।

आतंकवाद पर भारत का सख्त संदेश

प्रतिनिधिमंडल यह भी बताएगा कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने नागरिक और सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाया। हाल ही में भुज एयरफोर्स स्टेशन की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा।

सात अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल, अलग-अलग देश

हर देश के लिए अलग–अलग प्रतिनिधिमंडल होंगे जिनमें 5दृ6 सांसद शामिल रहेंगे और 10 दिन का दौरा तय किया गया है। प्रतिनिधिमंडलों में कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके, बीजेडी, माकपा आदि दलों के सांसद भाग लेंगे।

प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की सूची

भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया गया है। ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख सहयोगी देशों का दौरा करेंगे। ये भारत की श्जीरो टॉलरेंस फॉर टेररश की नीति को प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित नेता करेंगे:

- शशि थरूरः कांग्रेस
- रविशंकर प्रसादः भाजपा
- संजय कुमार झाः जदयू
- बैजयंत पांडाः भाजपा
- कनिमोझी करुणानिधिः डीएमके
- सुप्रिया सुलेः एनसीपीश्रीकांत एकनाथ शिंदेः शिवसेना

यूपी की राजनीति में गिरती भाषा और बढ़ती ट्रोल नीति

यह मामला न सिर्फ एक राजनीतिक टकराव का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार डिजिटल युग में राजनीतिक दलों की ओर से किए गए पोस्ट सीधे सामाजिक सौहार्द, नैतिक मर्यादा और राजनीतिक विमर्श की गरिमा पर असर डाल सकते हैं।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के दिनों में जिस तरह की तीखी बयानबाजी और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली बहसों ने तूल पकड़ा है, उसमें सबसे हालिया और विवादास्पद मामला समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी है।

यह मामला न सिर्फ एक राजनीतिक टकराव का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि किस प्रकार डिजिटल युग में राजनीतिक दलों की ओर से किए गए पोस्ट सीधे सामाजिक सौहार्द, नैतिक मर्यादा और राजनीतिक विमर्श की गरिमा पर असर डाल सकते हैं। 16 मई को सपा मीडिया सेल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बृजेश पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस पोस्ट में उपमुख्यमंत्री की तुलना सोनागाछी और जीबी रोड जैसे देश के रेड लाइट एरिया से जोड़ते हुए यह कहा गया कि उनका डीएनए इन क्षेत्रों में नियमित रूप से आने वाले लोगों से मिलाया जाना चाहिए, ताकि उनकी वास्तविक पहचान सामने आ सके। पोस्ट में जिस प्रकार के शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, वह न केवल अभद्र था, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों के प्रति भी एक अपमानजनक दृष्टिकोण को उजागर करता है।

हालिया और विवादास्पद मामला समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी है।

यही कारण था कि इस पोस्ट को लेकर तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई और बृजेश पाठक ने स्वयं इसे अपनी दिवंगत माता–पिता का अपमान बताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से पूछा कि क्या यही

उनकी पार्टी की भाषा है।

बृजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस स्तर की मानसिकता का परिचय इस पोस्ट के माध्यम से दिया है, वह न केवल स्त्री विरोधी है बल्कि पतित सोच को भी दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में विचारों का विरोध होता है, लेकिन किसी के चरित्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले करना राजनीति को गटर में ले जाने जैसा है। उन्होंने अखिलेश यादव से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या यह उनकी पार्टी की अधिकृत नीति है या किसी असंतुलित व्यक्ति की निजी राय, जिसे पार्टी ने अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि समाजवाद के नाम पर सपा जिन बातों को बढ़ावा दे रही है, वह केवल गाली–गलौच, जातिगत विद्वेष और अनैतिक आचरण का पर्याय बन चुका है। इस पूरे मामले ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी सक्रिय कर दिया। लखनऊ महानगर भाजपा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में यह कहा गया कि यह पोस्ट न केवल जातीय विद्वेष फैलाने वाली है, बल्कि महिलाओं का घोर अपमान करती है और समाज में आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करती है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव का पुतला जलाया और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस प्रकार की अभद्रता के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई सार्वजनिक माफी नहीं मांगी जाती, तो वे आंदोलन तेज करेंगे।

वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से संयमित भाषा का प्रयोग करने को कहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि उपमुख्यमंत्री को भी अपनी भाषा और व्यवहार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में यदि सत्ता पक्ष की ओर से निरंतर अनर्गल आरोप लगाए जाएंगे, तो विपक्षी कार्यकर्ताओं में भी प्रतिक्रिया की भावना उत्पन्न होगी। अखिलेश का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि वे इस मामले में पूरी तरह सपा की सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हैं और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि भाजपा को ऐसी टिप्पणियों से आपत्ति है तो उन्हें भी अपने नेताओं के बयानों की जांच करनी चाहिए।

बृजेश पाठक ने इसके जवाब में अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाजवाद की प्रयोगशाला नहीं, बल्कि गाली–गलौच की प्रयोगशाला बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस डॉ. राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों को सपा अपनाने का दावा करती है, उनकी आत्मा इस तरह के कृत्यों से व्यथित होगी। पाठक ने यह भी कहा कि राजनीति में नैतिकता और शालीनता होनी चाहिए, लेकिन सपा नेतृत्व ने अब इसे पूरी तरह ताक पर रख दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यदि विपक्षी दलों को लगता है कि सत्ता पक्ष की नीतियों में कोई त्रुटि है, तो उन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पर जाकर अनर्गल आरोप लगाने चाहिए।

यह प्रकरण न सिर्फ एक राजनेता के मान–सम्मान से जुड़ा है, बल्कि यह पूरे लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी सवाल खड़ा करता है। सोशल मीडिया आज राजनीति का एक अत्यंत प्रभावशाली मंच बन चुका है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक दलों की ओर से इस मंच का उपयोग अब मर्यादाहीन और असंयमित भाषा के लिए किया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। यह केवल एक दल या एक नेता का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक विमर्श की गिरती गुणवत्ता का प्रमाण है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में स्वस्थ आलोचना एक अनिवार्य तत्व होती है, लेकिन जब यह आलोचना निचले स्तर पर जाकर निजी जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जातिगत पहचान पर केंद्रित हो जाए, तो इससे न केवल राजनीतिक वातावरण दूषित होता है, बल्कि आम जनता के बीच भी राजनीति के प्रति विश्वास में गिरावट आती है।

इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को अपने सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि वैचारिक परिपक्वता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए। यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया टीमों को केवल पार्टी लाइन का प्रचार करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाए कि भाषा की मर्यादा और समाज की संवेदनाओं का आदर किस प्रकार किया जाता है। इस दिशा में अगर सख्ती नहीं बरती गई, तो आने वाले समय में राजनीतिक संवाद केवल ट्रोल संस्कृति में सिमटकर रह जाएगा। साथ ही यह मामला महिलाओं के प्रति सम्मान और सामाजिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से पोस्ट में रेड लाइट क्षेत्रों और वहाँ काम करने वाली महिलाओं को उपहास का माध्यम बनाया गया, वह स्त्री विरोधी मानसिकता की ओर इशारा करता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात करने वाले दल यदि इस प्रकार की अभद्रताओं को संरक्षण देते हैं, तो यह न केवल पाखंड है बल्कि उस समावेशी समाज के खिलाफ एक सीधा प्रहार है जिसकी कल्पना संविधान करता है।

आखिरकार यह पूरा विवाद इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय राजनीति को अब विचारधारा की बजाय ट्रोलिंग और बदजुबानी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। यह जरूरी है कि देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, इस प्रवृत्ति पर गंभीर आत्ममंथन करें। राजनीतिक विमर्श को गरिमामय बनाना केवल भाषणों और घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि वह नेताओं और उनके संगठनों की वास्तविक नीयत और कार्यशैली से प्रकट होगा। अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संभावना प्रबल है कि राजनीति में वैचारिक संघर्ष के स्थान पर व्यक्तिगत अपमान और नैतिक पतन ही मुख्य हथियार बन जाएंगे। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत होगा और इसका दुष्परिणाम देश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा।

पता नहीं कब तक रहेंगी सरहदों की दूरियां...

ज्योति की डायरी से पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा

कुल 10 पन्नों में विभिन्न देशों की जानकारी संकलित है, जिनमें से तीन पेज पाकिस्तान यात्रा को समर्पित हैं। ये तीनों पृष्ठ हिंदी में हैं, जबकि अन्य आठ अंग्रेजी में लिखे गए हैं। डायरी में महाभारत, रामायण, रजिया सुल्तान, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलते हैं।

हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के घर से मिली एक डायरी ने पाकिस्तान यात्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियों का खुलासा किया है। इस डायरी में जहां उसने अपनी भावनाओं को दर्ज किया है, वहीं पाकिस्तान से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी लिखे हैं जो हैरान कर सकते हैं। ज्योति की यह डायरी साल 2012 की है, जिसमें यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ-साथ उसके अनुभव और मन की बातें भी दर्ज हैं।

कुल 10 पन्नों में विभिन्न देशों की जानकारी संकलित है, जिनमें से तीन पेज पाकिस्तान यात्रा को समर्पित हैं। ये तीनों पृष्ठ हिंदी में हैं, जबकि अन्य आठ अंग्रेजी में लिखे गए हैं। डायरी में "महाभारत", "रामायण", "रजिया सुल्तान", "कुतुब मीनार" जैसे ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलते हैं।

हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं...

ज्योति ने अपनी डायरी में लिखा है:

ष्पाकिस्तान में 10 दिन बिताकर वापस अपने वतन लौट आई हूं। वहां की आवाम से बहुत मोहब्बत मिली। लाहौर घूमने के लिए दो दिन बहुत कम लगे। पता नहीं सरहदों की दूरियां कब तक कायम रहेंगी, पर दिलों के गिले-शिकवे मिट जाएं। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। अगर कुछ ऐसा है जो वीडियो में नहीं बताया, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं।

बंटवारे का दर्द भी उभारा

ज्योति ने पाकिस्तान सरकार से अपील करते हुए लिखा:

हिंदू श्रद्धालुओं के लिए और गुरुद्वारे-मंदिर खोलें, ताकि 1947 में बिछड़े परिवार फिर मिल सकें।

उसने पाकिस्तान की बसों को ष्क्रेजी एंड कलरफुलष बताया और अपने परिवार के बंटवारे की पीड़ा को भी साझा किया। बताया कि उसका परिवार बंटवारे के समय पाकिस्तान से फरीदकोट आया और फिर हिसार में बसा।

पिता अवसाद में, घर बिखरा पड़ा

ज्योति की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता हरीश मल्होत्रा गहरे सदमे में हैं। घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। उनके पास न स्मार्टफोन है और न ही वे पढ़े-लिखे हैं। वह बेटी की शादी के सपने देख रहे थे, अब निराशा से घिरे हुए हैं।

एनआईए की सात घंटे की पूछताछ ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। एनआईए ने उससे पहलगाम आतंकी हमले के संभावित संबंध को लेकर करीब सात घंटे तक पूछताछ की। एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या उसके पाकिस्तान दौरे और जनवरी 2025 में पहलगाम यात्रा का कोई लिंक है। उसकी बार-बार पाकिस्तान यात्रा, पहलगाम में असामान्य समय पर उपस्थिति, पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने वाले वीडियो और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित कंटेंट, सब कुछ जांच के दायरे में है।

पुलिस ने घर से लैपटॉप–मोबाइल जब्त किया। ज्योति का मोबाइल और लैपटॉप एफएसएल, मधुबन भेजा गया है, जहां उसके डेटा की गहन जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कई राज सामने आने की उम्मीद है।

जो आतंकवादियों की मदद करे, वह भारतीय नहीं हो सकता

पहलगाम आतंकी हमले के बाद ज्योति ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि यदि किसी ने आतंकियों की मदद की है, तो वह भारतीय नहीं कहलाने लायक है।

लब्बोलुआब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के

पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने वाले वीडियो और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित कंटेंट, सब कुछ जांच के दायरे में है।

विभिन्न निर्णयों से स्पष्ट होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और इसे अन्य अधिकारों और समाज के हितों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। अदालत के फैसले इस संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हालांकि इन निर्णयों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से बहस और आलोचना होती रही है। इससे इतर सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कभी काफी सख्त को कभी बेहद नरम नजर आता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो,लेकिन वह विवादित शेरों शायरी से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी वह माफिया अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ने के चलते भी विवादों में रह चुके हैं।

शायरी के जरिये सियासत की दुनिया में दाखिल होने वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ वर्ष पूर्व प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान खतरनाक गुंडे अतीक अहमद की जमकर तारीफ की थी। इमरान प्रतापगढ़ी, अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ते हुए कह रहे हैं कि,'इलाहाबाद वालों मेरी एक बात याद रखना, कई सालों तक कोई अतीक अहमद होगा। मुझे इस बात का अंदाजा है कि एक शख्स इस शहर में बैठा यही, जो सबकुछ संभाल लेगा।' प्रतापगढ़ी ऐसी ही शेरो शायरी माफिया मुख्तार अंसारी की शान में भी पढ़ चुके थे,जिसकी चंद लाइनों मे उन्होंने अपने को मुख्तार के रूप में पेश करते हुए कहा था,' एक पटाखा भी फोड़ा तो बम लिख दिया, जितनी मोहब्बत है इस मुल्क से, उससे कहीं ज्यादा मैं वफादार हूं। हाँ मैं मुख्तार हूँ, हाँ मैं मुख्तार हूँ।

पूर्व सीजेआई चन्द्रचूड़ के गले की फांस बना तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देना

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और विवादास्पद निर्णय सामने आए, जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनके कुछ निर्णयों और दृष्टिकोणों ने सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है, 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में साक्ष्य गढ़ने और गवाहों को प्रभावित करने के आरोप में जेल में बंद तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देना पूर्व न्यायाधीश के लिये गले की फांस बनता नजर आ रहा है, क्योंकि यह मामला राष्ट्रपति के पास एक शिकायत के रूप में पहुंच चुका है, जिसकी जांच का आदेश भी राष्ट्रपति ने कानून मंत्रालय को दे दिया है।

तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में साक्ष्य गढ़ने और गवाहों को प्रभावित करने के आरोप हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था । हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन रात में एक विशेष सुनवाई में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी। इतना ही नहीं तीस्ता को जमानत मामले की सुनवाई के लिये पहले दो जजो की बेंच बनाई गई, लेकिन इसमें से जब एक जज ने सवाल खड़ा किया कि इतनी जल्दी क्या है जमानत देने की तो मामला फंसता देख तत्कालीन मुख्य

न्यायाधीश ने तीन चचों की बेंच बना दी जिसने तीस्ता को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की तीन–न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल थे, ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को पूर्णतः विकृत और विरोधाभासी करार दिया। पीठ ने यह भी कहा कि सीतलवाड़ की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी हैं और पहले ही जांच एजेंसी के पास हैं

एक पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के मानकों के खिलाफ है और इससे न्यायपालिका की साख पर प्रश्नचिह्न लगता है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे न्यायिक निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है। शिकायतकर्ता का कहना है यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और कार्यपालिका के साथ उसके संबंधों पर व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। राष्ट्रपति को भेजी गई शिकायत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, जो न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

चन्द्रचूड़ के अन्य विवादित फैसलों की बात की जाये तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट की

एक पूर्व न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के मानकों के खिलाफ है और इससे न्यायपालिका की साख पर प्रश्नचि लगता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे न्यायिक निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है।

पांच–न्यायाधीशों की एक पीठ ने 4–1 के बहुमत से आधार योजना को संवैधानिक घोषित किया।

हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने 481 पृष्ठों के असहमति वाले निर्णय में आधार अधिनियम को संविधान पर धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को मनी बिल के रूप में पारित करना द्वि–सदनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन है और यह नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार का हनन करता है।

2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने असहमति जताते हुए कहा कि पुलिस जांच में पक्षपात की संभावना है और एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन होना चाहिए। उन्होंने मीडिया में जांच से संबंधित जानकारी के लीक होने को भी जांच की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करने वाला बताया। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस निर्णय में सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने असैनसियल रीजनल प्रैक्टिस के सिद्धांत पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) का उल्लंघन है।

2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने आंशिक असहमति वाले निर्णय में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है।

2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस निर्णय में कहा कि गोपनीयता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। इस निर्णय ने बाद में धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने का मार्ग प्रशस्त किया।

2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम यानि आरटीआई के तहत आता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस निर्णय में सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका की पारदर्शिता और स्वतंत्रता एक–दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ चल सकते हैं।

2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार करते हुए कहा कि किसी संस्थान की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई हो, तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है। इस निर्णय ने 1967 के अजीज बाशा मामले को पलट दिया।

सेना के साथ खड़ा भारत, सत्ता के लिए लड़ता पाकिस्तान

भारत के लिये यह सुखद है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के हर कदम पर विपक्ष बिना किसी शर्त के पूरी मजबूती से खड़ा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया है।

संजय सक्सेना,
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में जिस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर तलवारें खींची नजर आती थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से दोनों धड़ों में एकजुटता देखने को मिल रही है, उससे देश की आम जनता काफी खुश है, वहीं पाकिस्तान में इसके उलट नजारा नजर आ रहा है। पड़ोसी मुल्क में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसने और उन्हें नाकाबिल नेता साबित करने में लगा है। मोदी और शरीफ की तुलना शेर और सियार के रूप में की जा रही है।

बहरहाल, भारत के लिये यह सुखद है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के हर कदम पर विपक्ष बिना किसी शर्त के पूरी मजबूती से खड़ा है। जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया है। विपक्षी दलों ने इस बार न केवल सरकार का समर्थन किया बल्कि सेना के साहस और कार्रवाई की खुलकर सराहना की। इससे पहले उरी और पुलवामा हमलों के बाद जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी खांचे में रखकर सियासी नुकसान पहुंचाया था, उस पृष्ठभूमि में यह बदलाव बेहद अहम है। यह न केवल राजनीति की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब एक स्वर में बोल रहा है।

गौरतलब हो, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले ने न केवल आम जनता की भावनाओं को आहत किया, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी थी कि वे इस मुद्दे को किस रूप में लें। कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों ने बिना देर किए केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की संभावित चूक का मुद्दा उठाने के बावजूद, इसे राजनीति का विषय नहीं बनने दिया। यह देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए विपक्ष का एक परिपक्व और जिम्मेदार रवैया था।

भारतीय सेना ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक और प्रभावशाली कार्रवाई की। सेना की इस जवाबी कार्रवाई को विपक्ष की ओर से न केवल समर्थन मिला बल्कि सराहना भी हुई। कोई सवाल नहीं, कोई प्रमाण की मांग नहीं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं बस एक सुर में सरकार और सेना के साथ खड़े रहने की भावना। 'भारत माता की जय' और 'जय हिंद' के नारों के साथ विपक्षी नेता भारतीय सेना के साथ नजर आए। यह एक ऐसी तस्वीर थी जो 2016 के उरी हमले या 2019 के पुलवामा हमले के बाद नजर नहीं आई थी।

उरी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करके राजनीतिक लाभ उठाया था। ठीक ऐसा ही पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे, जिसके चलते पार्टी को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने भी सेना के शौर्य पर विश्वास जताने के साथ–साथ पीएम मोदी पर जवानों के बलिदान की राजनीति करने का आरोप

विपक्षी दलों ने इस बार न केवल सरकार का समर्थन किया बल्कि सेना के साहस और कार्रवाई की खुलकर सराहना की।

लगाया था। इन बयानों से कांग्रेस को चुनावी मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रोक दिया, पार्टी की सर्वाच्च नीति–निर्धारण संस्था कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक बुलाई गई और राहुल गांधी ने स्वयं सेना को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के सुझाव पर कांग्रेस ने अपनी "संविधान बचाओ" रैली स्थगित कर दी, ताकि सेना के प्रति एकजुटता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश स्पष्ट रूप से जाए। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस ने भी अपनी उस सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया, जिसमें शांति को सबसे बड़ा हथियार बताया गया था जो शायद मौजूदा माहौल में सेना के ऑपरेशन के संदर्भ में गलत संदेश दे सकती थी।

कांग्रेस के इस नए रुख के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी उसी दिशा में नजर आए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात करके अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने की घोषणा की। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी, जो अक्सर मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को 'एक मजबूत शुरुआत' बताया और सेना की निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी के शब्दों की आलोचना कर चुके थे, उन्होंने भी इस बार सेना के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश एकजुट है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की और जवानों को सलाम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अक्सर मोदी सरकार के आलोचक रहते हैं, उन्होंने भी इस बार सरकार के सुर में सुर मिलाया और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। यहां तक कि वामपंथी दलों ने, जो आमतौर पर सैन्य कार्रवाई पर संयम बरतने की बात करते हैं, उन्होंने भी पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना के साथ खड़े होने की बात कही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने भी माना कि इस बार भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए एक नई दिशा का संकेत है। यह दर्शाता है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर अब राजनीतिक दल न केवल एकजुट हैं, बल्कि अपने पुराने सियासी रवैये की भी समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का यह नया रुख जहां उसे राष्ट्रवादी विमर्श में खुद को फिट करने में मदद करेगा, वहीं अन्य विपक्षी दलों के लिए भी यह संदेश है कि जनता अब केवल आरोप–प्रत्यारोप नहीं, बल्कि एकजुटता और जिम्मेदारी की राजनीति देखना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति न तो नरम है, न ही विभाजित। यह केवल केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि विपक्ष की परिपक्व भागीदारी का भी प्रतिबिंब है। अगर इस रुख को भविष्य में भी कायम रखा गया, तो यह न केवल देश की आंतरिक राजनीति को परिपक्व बनाएगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की छवि को और सुदृढ़ करेगा।

बात पाकिस्तान की कि जाये तो वहां सेना, सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खींची हुई हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक स्थिति डगमगाई हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सियासत भी बुरी तरह बिखर गई है। जब देश को एकजुट होकर संकट का सामना करना चाहिए, तब पाकिस्तानी नेता एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच बढ़ती खींचतान ने पूरे मुल्क को असमंजस में डाल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने मौजूदा सरकार पर सेना के साथ मिलीभगत और गलत फैसलों का आरोप लगाया है, वहीं सरकार का कहना है कि इमरान खान जैसे नेता युद्ध के समय भी राष्ट्रविरोधी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। संसद में तीखी बहस के दौरान विपक्षी नेताओं ने सेना की विफलताओं पर सवाल खड़े किए, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि और कमजोर हुई। इस बीच, पाकिस्तानी सेना और सरकार के बीच भी समन्वय की कमी साफ नजर आ रही है। मीडिया के मुताबिक, कई रक्षा फैसलों पर सेना और सरकार की राय अलग–अलग रही है, जिससे फ्रंट पर रणनीतिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे देश के आम नागरिकों में असुरक्षा और निराशा का माहौल है। जानकार मानते हैं कि इस समय पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत से नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई राजनीतिक नेतृत्व और कमजोर रणनीतिक सोच से है।

विराट कोहली का टेस्ट संन्यास

हर रन था जुनून, हर पारी एक जंग

टेस्ट क्रिकेट, जिसे क्रिकेट का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है, वहां कोहली ने खुद को एक योद्धा की तरह साबित किया। विराट कोहली जुनून, अनुशासन और आक्रामकता के प्रतीक भर नहीं थे। उनकी विदाई सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं है, यह एक भावना का अंत है।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

महान क्रिकेट खिलाड़ी और हर फारमेट में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके रोहित शर्मा के बाद उनके हम सफर एवं समकक्ष एक और बड़े खिलाड़ी विराट कोहली ने भी 14 वर्षों के बाद टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया है। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में एक सदी का अंत हो गया, एक युग पर पूर्णविराम लग गया। जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा की, तो न केवल क्रिकेट जगत, बल्कि करोड़ों भारतीय फैंस की आंखें नम हो गईं। टेस्ट क्रिकेट, जिसे क्रिकेट का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है, वहां कोहली ने खुद को एक योद्धा की तरह साबित किया। विराट कोहली जुनून, अनुशासन और आक्रामकता के प्रतीक भर नहीं थे। उनकी विदाई सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं है, यह एक भावना का अंत है।

विराट कोहली का टेस्ट करियर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हुआ। शुरुआती असफलताओं के बावजूद, उन्होंने जल्द ही दिखा दिया कि उनके अंदर खास बात है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 की श्रृंखला में उनका शतक, इंग्लैंड में 2018 में पारी दर पारी लड़ना, और दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतने की जिद को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अपना रण बना लिया था। कप्तानी के तौर पर भी कोहली ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 68 टेस्ट में कप्तानी की, जिनमें से 40 में भारत को जीत दिलाई। यह एक भारतीय कप्तान के रूप में सर्वाधिक है। विदेशी धरती पर भारत की टेस्ट जीत, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में 2018 और इंग्लैंड में चुनौतीपूर्ण ड्रॉ, कोहली की आक्रामक नेतृत्व शैली की पहचान बन गई।

कोहली के टेस्ट करियर के आंकड़े शानदार हैं। 113 टेस्ट, 8845 रन, 29 शतक और 29 अर्धशतक विराट के नाम हैं। लेकिन जो चीज उन्हें आंकड़ों से ऊपर उठाती है, वह है

विराट ने जब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टेस्ट सन्यास की घोषणा की, तो शब्दों से ज्यादा भावनाएं थीं। उन्होंने लिखा, "यह खेल मुझे सब कुछ दे गया, लेकिन अब समय है कि मैं अगली पीढ़ी को स्थान दूं। मैंने अपना दिल और आत्मा इस प्रारूप को दिया है। अब मुझे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना है।"

उनकी मानसिक दृढ़ता और खेल के प्रति निष्ठा। विराट ने टेस्ट क्रिकेट को ताज की तरह पहना। जिस दौर में टी 20 और आईपीएल के चकाचौंध ने युवाओं का ध्यान खींचा, कोहली टेस्ट को 'बेस्ट फॉर्मेट' मानते रहे। वह अक्सर कहते थे कि अगर आपको एक असली बल्लेबाज बनना है, तो टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा।

यह कहना अतिशियोक्ति नहीं है, कि कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक लीडर थे। उनकी आक्रामकता ने टीम इंडिया को नया तेवर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों को डर से नहीं, प्रेरणा से नेतृत्व किया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को टेस्ट में हथियार बनाना, और अजिंक्या रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा करना कोहली की रणनीतिक सूझबूझ का हिस्सा था। विराट ने फिटनेस संस्कृति को भारतीय टीम में जड़ से बदल दिया। 'यो–यो टेस्ट' को अनिवार्य करना, खुद को हर मैच के लिए तैयार रखना, और दूसरों से भी वही उम्मीद रखना, यही विराट का मानक था। उनके लिए भारतीय टीम सिर्फ एक जर्सी नहीं थी, वह एक जज्बा था।

विराट ने जब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टेस्ट सन्यास की घोषणा की, तो शब्दों से ज्यादा भावनाएं थीं। उन्होंने लिखा, "यह खेल मुझे सब कुछ दे गया, लेकिन अब समय है कि मैं अगली पीढ़ी को स्थान दूं। मैंने अपना दिल और आत्मा इस प्रारूप को दिया है। अब मुझे अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करना है।" फैंस के लिए यह खबर बिजली की तरह थी। चाहे चेन्नई हो या मेलबर्न, लॉर्ड्स हो या कोलकाता, हर मैदान जहां विराट ने गगनभेदी गर्जना की, आज शांत था। स्टेडियम की भीड़, जिनके "कोहली, कोहली" के नारे आसमान गूंजते थे, अब एक आखिरी बार खड़े होकर सलाम कर रही थी।

खैर, बात विराट के सन्यास के बाद के टेस्ट क्रिकेट की की जाये तो टेस्ट मैच से विदाई के बाद भी विराट कोहली भारतीय क्रिकेट से दूर नहीं होंगे। वह युवाओं के लिए प्रेरणा रहेंगे, मैदान पर नहीं तो उनके दिलों में। उनकी जीवटता, संघर्षशीलता और 'कभी न हार मानने' की भावना, अगली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक रहेगी। विराट की यात्रा सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। वे आज भी सोशल कार्यों, स्वास्थ्य, फिटनेस और युवा सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे एक खिलाड़ी अपने खेल से बाहर निकलकर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

लब्बोलुआब यह है कि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली के बिना अधूरा लगेगा,लेकिन उनकी विरासत हर युवा बल्लेबाज की आंखों में चमकेगी, हर गेंदबाज की चुनौती में दिखेगी और हर भारतीय फैन के दिल में धड़कती रहेगी। उन्होंने बल्ले से जो लिखा, वो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, इतिहास की किताबों

कांग्रेस अपने इस नेता को क्यों शक की नजर से देखती है?

कांग्रेस में जब अध्यक्ष पद के लिये चुनाव हुआ थो तो भी शशि थरूर ने गांधी परिवार की नाराजगी की चिंता किये बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी, यह बात गांधी परिवार को काफी बुरी थी लगी थी, इसी लिये कांग्रेस में थरूर को अब शक की नजर से देखा जाता है।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ

क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यह सवाल इस लिये उठ रहा है क्योंकि थरूर कई बार पार्टी की लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस में जब अध्यक्ष पद के लिये चुनाव हुआ थो तो भी शशि थरूर ने गांधी परिवार की नाराजगी की चिंता किये बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी, यह बात गांधी परिवार को काफी बुरी थी लगी थी, इसी लिये कांग्रेस में थरूर को अब शक की नजर से देखा जाता है।

खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही मिठास भरे नजर आ रहे हैं। जब भी दोनों नेता कहीं मिलते हैं या लोकसभा में आमना–सामना होता है भी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी इस दिग्गज कांग्रेस नेता को सम्बोधित करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ केरल के विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान देखने को मिला जब जब सांसद शशि थरूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही मंच पर दिखाई दिए। दोनों ने एक–दूसरे गरम जोशी से स्वागत किया। इस दृश्य ने न केवल स्थानीय राजनीति को बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की नींदें उड़ा दीं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी का व्यंग्यात्मक अंदाज, दूसरी ओर थरूर की सहज आत्मीयता, इस पूरे प्रसंग को सामान्य शिष्टाचार से कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक संकेत बना गई।

गौरतलब हो शशि थरूर कोई साधारण सांसद नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव, संयुक्त राष्ट्र में लंबी सेवा, शानदार वक्तव्य कला और साहित्यिक पृष्ठभूमि उन्हें एक ऐसा राजनेता बनाती है जो भीड़ में अलग दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका व्यक्तित्व अक्सर असहजता पैदा करता रहा है। उनके स्पष्ट विचार, खुले मंचों पर सरकार की तारीफ और खुद को पार्टी लाइन से ऊपर रखने की प्रवृत्ति उन्हें अक्सर 'अपनों' के बीच ही अजनबी बना देती है। विझिंजम पोर्ट कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी तो एक सांसद की भूमिका के तहत थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें साझा कीं और फिर सोशल मीडिया पर गर्व के साथ लिखा कि उन्हें इस परियोजना से शुरू से जुड़ने का सौभाग्य मिला है यह सब कुछ कांग्रेस को चुभने के लिए काफी था।

राजनीति में जो चीजें नजर आती हैं, वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं होतीं, जितनी कि उनके पीछे छिपे संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र

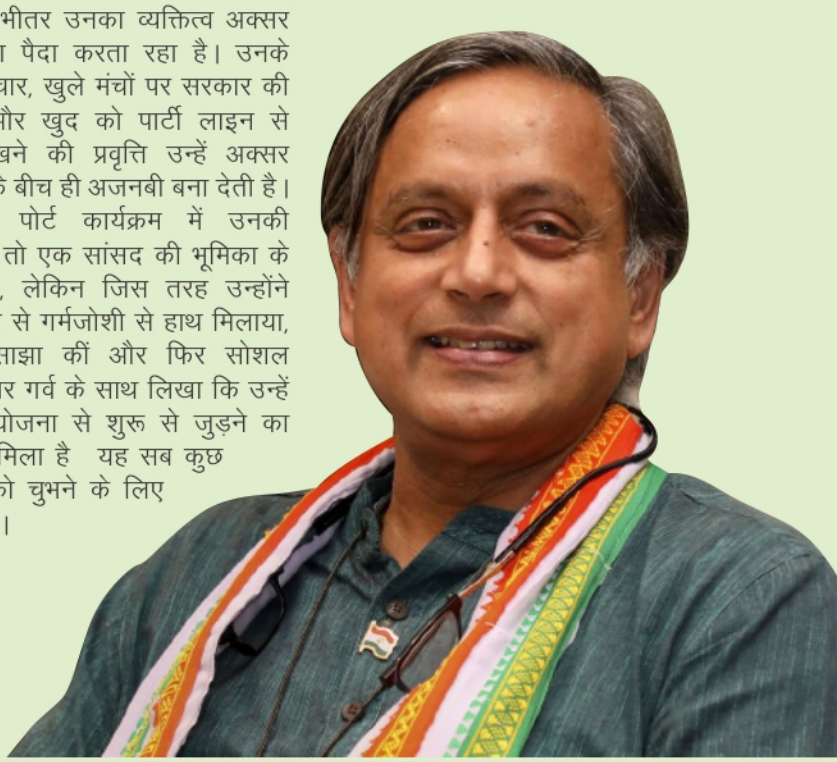

मोदी इस कला के उस्ताद हैं। मंच से उन्होंने व्यंग्य के लहजे में कहा कि यह आयोजन कई लोगों की नींद हराम कर देगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके संकेत स्पष्ट थे। राहुल गांधी, जो अक्सर प्रधानमंत्री की विदेश नीति नेतृत्व शैली की कटु आलोचना करते हैं, वहीं उनके ही पार्टी सहयोगी थरूर खड़े होकर इस ऐतिहासिक क्षण में प्रधानमंत्री का समर्थन करते दिखे। यह विरोधाभास कांग्रेस के लिए एक सियासी संकट बनता जा रहा है।

शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बढ़ती सार्वजनिक नजदीकियों की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वे रूस–यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत की नीति की सराहना कर चुके हैं। थरूर ने स्वीकार किया था कि उन्होंने पहले इस नीति की आलोचना की थी लेकिन बाद में यह मानना पड़ा कि मोदी सरकार ने कूटनीतिक संतुलन बेहतरीन तरीके से साधा। उन्होंने यहां तक कहा कि जब प्रधानमंत्री ने दो सप्ताह के भीतर रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और दोनों ने भारत को सम्मान दिया, तो वह क्षण गर्व का था। यह बयान कांग्रेस की आधिकारिक विदेश नीति आलोचना के बिल्कुल विपरीत था।

भाजपा को थरूर के इस बदले रुख में संभावनाएं दिख रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा कि प्रधानमंत्री को अब नए आलोचकों की जरूरत है क्योंकि

शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बढ़ती सार्वजनिक नजदीकियों की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वे रूस-यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत की नीति की सराहना कर चुके हैं। थरूर ने स्वीकार किया था

पुराने अब उनके प्रशंसक बनते जा रहे हैं। एक और भाजपा नेता बैजयंत जय पांडा ने शशि थरूर के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि वे और थरूर अब एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। शशि थरूर ने इस पर हल्के–फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी लेकिन यह संकेत कई लोगों के लिए बहुत गंभीर था।

थरूर की यह छवि कांग्रेस के भीतर लगातार चर्चा का विषय रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भले सार्वजनिक रूप से कुछ न कहें, लेकिन निजी तौर पर यह चिंता जरूर जताई जाती रही है कि थरूर अपनी स्वतंत्र सोच को पार्टी लाइन से ऊपर रख रहे हैं। जब हाल ही में जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद खुफिया तंत्र की आलोचना हो रही थी, तब थरूर ने कहा कि किसी देश की खुफिया एजेंसी सौ फीसदी प्रभावी नहीं हो सकती और उन्होंने इजरायल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी चूक होती है। इस बयान पर कांग्रेस के ही नेता उदित राज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि थरूर भाजपा सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि वे विपक्ष में हैं।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम से थरूर की जीत ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को हराया और भाजपा ने हार के बावजूद चंद्रशेखर को केरल का नेतृत्व सौंपा। इससे यह साफ है कि भाजपा थरूर को एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी मानती है और उन्हें अपने पक्ष में करने की हर संभावित रणनीति पर काम कर रही है। वहीं थरूर की रणनीति भी अब खुलकर सामने आ रही है वे यह दर्शा रहे हैं कि वे राष्ट्रहित में किसी की भी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वह प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों न हों।

यह घटनाक्रम सिर्फ एक राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संकट का भी संकेत देता है। थरूर जैसे नेता, जो लोकप्रिय हैं, मीडिया में प्रभावी हैं, वैश्विक सोच रखते हैं, वे पार्टी में हाशिए पर क्यों हैं? यह सवाल कांग्रेस को खुद से पूछना होगा। खुद थरूर ने फरवरी 2025 में कहा था कि अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प हैं। यह बयान हल्का नहीं था, यह एक चेतावनी थी।

भारतीय राजनीति अब तेजी से बदल रही है। विचारधारा से अधिक व्यक्ति का प्रभाव, चेहरे की पहचान और राष्ट्रहित में उठाए गए कदमों की अहमियत बढ़ गई है। ऐसे में थरूर जैसे नेता, जो बौद्धिक और व्यावहारिक राजनीति का मेल हैं, उन्हें लंबे समय तक पार्टी की आंतरिक राजनीति में उलझाकर नहीं रखा जा सकता। अगर कांग्रेस उन्हें अपना नहीं बना पाती, तो अन्य विकल्पों के लिए रास्ते खुले हैं।

विझिंजम पोर्ट पर मंच साझा करना महज शिष्टाचार नहीं था। यह एक राजनीतिक संदेश था थरूर की तरफ से भी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी। एक तरफ भाजपा केरल में जमीन तलाश रही है, दूसरी ओर थरूर दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि शशि थरूर कांग्रेस के भीतर रहकर ही पार्टी के कायाकल्प की उम्मीद रखते हैं या फिर उन्हें कोई नई राजनीतिक राह

कैंसर के इलाज में क्यों झड़ते हैं बाल? वैज्ञानिकों ने ढूंढ़ समाधान

कैंसर के इलाज से गुजर रहे मरीजों की एक आम शिकायत होती है, बाल झड़ना। खासकर कीमोथेरेपी लेने वाले मरीजों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब इस परेशानी को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका एक असरदार समाधान ढूंढ निकाला है।

कैंसर एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है, जिससे हर साल लाखों लोग जान गंवाते हैं। हालांकि चिकित्सा विज्ञान में हो रही प्रगति और नई तकनीकों के चलते अब इसका इलाज काफी हद तक संभव हो गया है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे इलाजों ने कैंसर को बढ़ने से रोकना आसान बना दिया है। लेकिन इन उपचारों के दौरान बाल झड़ना एक आम और मानसिक रूप से परेशान करने वाला दुष्प्रभाव है।

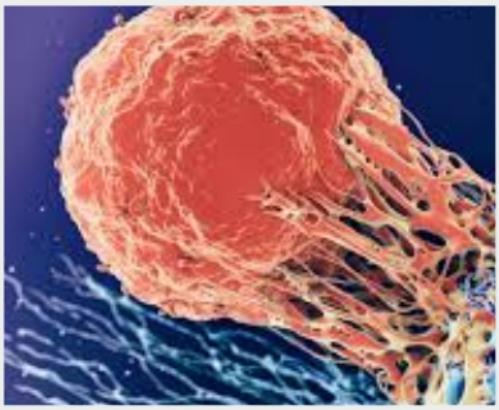

आखिर इलाज के दौरान बाल क्यों झड़ते हैं?

कीमोथेरेपी की दवाएं शरीर में तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को निशाना बनाती हैंकृजिसमें कैंसर कोशिकाओं के साथ–साथ बालों की जड़ें भी शामिल होती हैं। इस कारण बाल झड़ने लगते हैं। रेडिएशन थेरेपी भी इसी तरह से असर करती है। हालांकि सभी कीमोथेरेपी दवाएं बाल नहीं झाड़तीं, और इसका प्रभाव हर मरीज में अलग–अलग होता है।

स्कैल्प कूलिंग थेरेपी: बालों को बचाने की नई उम्मीद

अब वैज्ञानिकों ने श्स्कैल्प कूलिंग थेरेपीश नाम की एक तकनीक विकसित की है, जिससे कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ने की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस थेरेपी में मरीज को इलाज से पहले, दौरान और बाद में एक विशेष सिलिकॉन कैप पहनाई जाती है, जो सिर की सतह को ठंडा रखती है। इससे खोपड़ी में रक्त प्रवाह कम होता है और बालों की जड़ों तक कीमोथेरेपी दवाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है। डॉक्टरों के अनुसार, यह थेरेपी बालों को पूरी तरह झड़ने से रोकने की गारंटी तो नहीं देती, लेकिन क्लीनिकल परीक्षणों में पाया गया है कि इससे लगभग 70: तक बालों का झड़ना रोका जा सकता है। अमेरिका और यूरोप के 6,000 से अधिक केंद्रों में यह तकनीक पहले ही अपनाई जा चुकी है।

सिर्फ सौंदर्य नहीं, आत्मविश्वास से भी जुड़ा है यह मुद्दा

डॉक्टरों का मानना है कि बाल झड़ना केवल एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं हैकृयह मरीज की पहचान और आत्मविश्वास को भी गहराई से प्रभावित करता है। स्कैल्प कूलिंग से मरीजों को मानसिक रूप से सशक्त बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे वे इलाज की प्रक्रिया को ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना सकते हैं।

नोटरू कैंसर या किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज से जुड़ी जानकारी और निर्णय के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

मधुमेह के खतरे को कम करने के लिए स्कूलों में लगेंगे 'शुगर बोर्ड'

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त स्कूलों में अब जल्द ही 'शुगर बोर्ड' लगाए जाएंगे। सीबीएसई ने बच्चों में बढ़ती मधुमेह की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया है। इन बोर्डों के माध्यम से छात्रों को अत्यधिक चीनी सेवन, जंक फूड (जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज) और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों से होने वाले जोखिमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

स्कूलों में शुगर बोर्ड के जरिए जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें विशेषज्ञ बच्चों को अधिक चीनी सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देंगे। इस संबंध में सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड के अनुसार, पिछले एक दशक में बच्चों में टाइप–2 डायबिटीज के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पहले यह बीमारी मुख्यतः वयस्कों में पाई जाती थी, लेकिन अब बच्चों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। सीबीएसई का कहना है कि यह चिंताजनक प्रवृत्ति मुख्यतः स्कूलों में आसानी से मिलने वाले मीठे स्नैक्स, पेय पदार्थों और प्रोसेस्ड फूड के अधिक सेवन की वजह से देखी जा रही है।

अत्यधिक चीनी का सेवन न सिर्फ मधुमेह के खतरे को बढ़ाता है, बल्कि मोटापा, दांतों की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य विकारों का भी कारण बनता है, जो बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे शुगर बोर्ड लगाकर छात्रों को अधिक चीनी सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी दें। इन बोर्डों पर अनुशंसित दैनिक चीनी सेवन की मात्रा, आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा, और उनके स्वस्थ विकल्पों की जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

यह पहल छात्रों को बेहतर और जागरूक खाद्य विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वे शुगर बोर्ड की गतिविधियों से जुड़ी संक्षिप्त रिपोर्ट और तस्वीरें निर्धारित लिंक पर अपलोड करें। सीबीएसई का उद्देश्य एक स्वस्थ और जागरूक स्कूली वातावरण को बढ़ावा देना है। अध्ययनों के अनुसार, 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों की दैनिक कैलोरी का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा चीनी से आता है, जबकि 11 से 18 वर्ष के बच्चों में यह आंकड़ा 15 प्रतिशत तक है। जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, यह मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारत-पाक युद्ध के बाद ट्रंप की रणनीति में बदलाव दोस्ती या तकरार?

भारत के प्रति ट्रंप का रुख अब उतना दोस्ताना नहीं रह गया है। इसके पीछे कई भू-राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक कारण हैं जिनका प्रभाव दोनों देशों के संबंधों पर पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध के बाद ट्रंप के रुख में तेजी से बदलाव देखा गया।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच 2017 से 2021 तक का समय भारत–अमेरिका रिश्तों के लिए सुनहरा दौर माना गया था। दोनों नेताओं की दोस्ती की मिसाल 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे आयोजनों के जरिए दुनिया के सामने आई थी। ट्रंप ने उस समय मोदी को एक मजबूत नेता बताया था और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण माना था। लेकिन जब ट्रंप 2025 में एक बार फिर सत्ता में लौटे, तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत के प्रति ट्रंप का रुख अब उतना दोस्ताना नहीं रह गया है। इसके पीछे कई भू–राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक कारण हैं जिनका प्रभाव दोनों देशों के संबंधों पर पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध के बाद ट्रंप के रुख में तेजी से बदलाव देखा गया। उन्होंने खुद को युद्ध विराम का नायक बताते हुए दावा किया कि उनकी मध्यस्थता के कारण ही युद्ध रुका और परमाणु संघर्ष की नौबत नहीं आई। लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक द्विपक्षीय मामला है जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। भारत की इस प्रतिक्रिया से ट्रंप का अहं आहत हुआ और यही वजह है कि उनके बयानों में भारत के प्रति तल्खी साफ नजर आने लगी।

ट्रंप को यह बात भी खली कि भारत ने रूस–यूक्रेन युद्ध के दौरान तटस्थ रुख अपनाया और अमेरिका के लगातार आग्रह के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा। भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा जिससे न केवल वैश्विक तेल कीमतों पर असर पड़ा बल्कि अमेरिका को यह भी महसूस हुआ कि भारत उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं में पूरी तरह साथ नहीं दे रहा है। ट्रंप भले ही रूस के प्रति व्यक्तिगत रूप से नरम रुख रखते हों, लेकिन उन्होंने हमेशा यह चाहा कि अमेरिका के सहयोगी देश रूस और चीन के खिलाफ खुलकर खड़े हों। भारत का संतुलन बनाए रखना, ठत्प्ै और ैब् जैसे मंचों में सक्रिय रहना और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना ट्रंप को अखरने लगा। भारत और चीन के बीच व्यापार 125 अरब डॉलर के पार चला गया है जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत फन्।क जैसे मंचों के जरिए चीन का खुला विरोध करे।

इसके अलावा ट्रंप को पाकिस्तान के साथ अपने पुराने संबंधों को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। अमेरिका के रणनीतिक हलकों में यह समझ है कि पाकिस्तान की भू–राजनीतिक स्थिति उसे ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया पर प्रभाव बनाए रखने का जरिया बना सकती है। चीन और रूस के करीब गए

पाकिस्तान को वापस अपनी ओर खींचने की रणनीति के तहत अमेरिका ने प्डथ् से पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज दिलवाया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह धन आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया। यह घटनाक्रम भारत के लिए संकेत था कि अमेरिका अब पाकिस्तान को फिर से रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है।

ट्रंप ने भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' नीति को भी अपने व्यापारिक हितों के खिलाफ माना। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहते हुए आलोचना की और भारतीय निर्यात पर 10ः अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटा 30 अरब डॉलर से अधिक है, और ट्रंप को यह संतुलन खटकता है। भारत अपने बाजार की रक्षा के लिए अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है, जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, बादाम और सेब पर 50 से 100ः तक का शुल्क। ट्रंप का मानना है कि यह अमेरिकी व्यापार के लिए नुकसानदायक है और भारत को अपने नियमों में ढील देनी चाहिए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि व्यापार समझौते तभी होंगे जब वे पारस्परिक रूप से लाभकारी होंगे।

ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी सलाह दी कि वे भारत में आईफोन फैक्ट्रियों का विस्तार न करें और अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाएं। हालांकि एप्पल ने भारत में अपने निवेश को बनाए रखा क्योंकि भारत न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि सस्ते श्रम और व्यापारिक अवसरों की दृष्टि से आकर्षक गंतव्य भी है। भारत ने हाल के वर्षों में सौर उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है ताकि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। यह कदम ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से टकराता है क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। भारत के वैकल्पिक व्यापार समझौते जैसे यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ समझौते और त्ब्म् में फिर से विचार भारत की स्वतंत्र नीति को दर्शाते हैं जो अमेरिका के लिए असहज करने वाली है।

डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व में यह बात प्रमुख रही है कि वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी एक व्यापारिक सौदे की तरह देखते हैं। वे यह मानते हैं कि यदि किसी मुद्दे पर कोई नेता उनकी बात नहीं मानता या उनके प्रभाव को नकारता है, तो वह उनका विरोधी है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ युद्धविराम के लिए ट्रंप की मध्यस्थता को खारिज किया, वह ट्रंप के लिए सीधा झटका था। वह चाहते थे कि भारत भी पाकिस्तान की तरह उनके प्रयासों की सराहना करे, लेकिन भारत ने न केवल चुप्पी साधी, बल्कि बाद में यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। यह घटनाक्रम ट्रंप को निजी रूप से आहत कर गया और इसके बाद उनके बयानों में भारत के प्रति तल्खी और पाकिस्तान के प्रति नरमी का स्पष्ट अंतर देखा गया।

ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भी कई बार मध्यस्थता की बात की है जिसे भारत ने बार–बार खारिज किया। नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान से बात केवल पीओके और आतंकवाद पर ही होगी। इस बयान को अमेरिका में अच्छी नजरों से नहीं देखा गया क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को नकारने जैसा था। ट्रंप के लिए यह न केवल राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत अस्वीकार्यता भी थी क्योंकि वे खुद को दुनिया का सबसे प्रभावशाली सौदेबाज मानते हैं।

इन तमाम मुद्दों के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता बनाए रखी है और यह बात ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से टकराती है। ट्रंप चाहते हैं कि जो देश अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं, वे उसकी प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें, लेकिन भारत ने अपनी नीतियों को पूरी तरह स्वायत्त रखा है। भारत का जी–20, आई–2–यू–2, ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों में नेतृत्व करना, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना और किसी एक ध्रुव पर निर्भर न रहना अमेरिका के लिए एक चुनौती बन गया है। ट्रंप को यह लगता है कि भारत अब वह सहयोगी नहीं रहा जो अमेरिका के हर निर्देश पर चले, और यही वजह है कि उनका रवैया कठोर होता जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में यह समझना जरूरी है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध किस दिशा में जाएंगे। यदि ट्रंप की नीति कठोर बनी रही और भारत अपनी स्वतंत्रता पर अडिग रहा, तो यह दूरी और बढ़ सकती है। लेकिन दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक हित इतने गहरे हैं कि संवाद और सहयोग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भारत और अमेरिका दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक–दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों देश आपसी मतभेदों को पार करके समान हितों की पहचान कर पाएं, तो यह साझेदारी फिर से नई ऊंचाइयों को छू सकती है। लेकिन फिलहाल के हालातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की आंखों में भारत अब पहले की तरह नहीं भाता और इसके पीछे केवल एक कारण नहीं बल्कि पूरा अंतरराष्ट्रीय समीकरण खड़ा है, जिसे केवल समय ही सुलझा सकता है।

राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित करणी माता मंदिर

आस्था, अद्भुत परंपराएं और चूहों का अद्वितीय संसार

राजस्थान की भूमि अपने गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और रहस्यमयी धार्मिक स्थलों के लिए जानी जाती है। इन्हीं स्थलों में एक है बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित करणी माता मंदिर, जिसे आमतौर पर श्चूहों का मंदिरश कहा जाता है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि अपनी अनूठी परंपराओं के कारण विश्वभर के पर्यटकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है।

इतिहास की गहराइयों से...

माना जाता है कि करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 में जोधपुर के चारण वंश में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा, पशु संरक्षण और धार्मिक चेतना फैलाने में बिताया। करणी माता ने बीकानेर और जोधपुर जैसे राजघरानों को राजनीतिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया, जिससे इन राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। देशनोक को उन्होंने अपनी साधना भूमि बनाया और यहीं उनकी स्मृति में भव्य मंदिर की स्थापना की गई।

चूहों का रहस्यमयी संसार

इस मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता यहां निवास करने वाले लगभग 20,000 चूहे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में "काबा" कहा जाता है। ये चूहे श्रद्धालुओं के बीच पूजनीय हैं और इन्हें करणी माता के वंशजों का पुनर्जन्म माना जाता है। किंवदंती के अनुसार, करणी माता ने मृत्यु के देवता यमराज से अपने परिवार के लोगों के लिए पुनर्जन्म का अधिकार मांगा था ताकि वे उनके साथ रह सकें। यमराज की स्वीकृति के बाद उनके अनुयायी चूहों के रूप में मंदिर में रहने लगे।

आस्था में रची-बसी परंपराएं

मंदिर में रोजाना सुबह और शाम आरती के समय चूहों की सहभागिता देखना एक दिव्य अनुभव होता है। भक्त न केवल चूहों को प्रसाद खिलाते हैं, बल्कि उनके जूठे भोजन को भी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। यहां तक कि मंदिर की रसोई में काम करने वाले कर्मचारी और चूहे एक ही थाली में भोजन करते हैं, जो समभाव और आस्था का अनूठा उदाहरण है।

चूहों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। मंदिर परिसर में बिल्लियों या अन्य शिकारियों से सुरक्षा के लिए जालियां लगाई गई हैं। भक्त मंदिर परिसर में बेहद सावधानी से चलते हैं, ताकि किसी चूहे को गलती से भी चोट न लगे। यदि किसी चूहे की अनजाने में मृत्यु हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति चांदी या सोने का चूहा बनवाकर की जाती है।

वास्तुकला और धार्मिक प्रतीक

मंदिर की राजपूत शैली में निर्मित वास्तुकला, संगमरमर के नक्काशीदार द्वार, चांदी के किवाड़ और सोने का छत्र इसे भव्यता प्रदान करते हैं। गर्भगृह में स्थित माता की मूर्ति एक गुफा में स्थापित है, जहां करणी माता तपस्या किया करती थीं। यह स्थान आज भी भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है।

मेले और अनुष्ठान

वर्ष में दो बारकृचैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में यहां विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। साथ ही, 'ओरण परिक्रमा' नामक 42 किमी लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रि में की जाती है, जिसे अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय पहचान

करणी माता मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसे अमेरिकी रियलिटी शो "The Amazing Race" और डॉक्यूमेंट्री "Rats" में भी दिखाया गया है, जिससे इसे वैश्विक पहचान मिली है।

करणी माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का प्रतीक है। यह मंदिर दर्शाता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो, तो जीवन के हर रूप में ईश्वर के दर्शन संभव हैं: चाहे वह रूप इंसान का हो या एक चूहे का।

मेरा पन्ना

सरकारी स्कूलों के बच्चे

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

सरकारी स्कूलों के बच्चे
नहीं होते मक्खन
मथना पड़ता है उन्हें
नहीं हैं पीछे
प्राइवेट स्कूल के बच्चों से
सीखते हैं वो उनके अनुसार
उनके माहौल के अनुसार
प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढते हैं
प्लेग्रुप, एलकेजी, यूकेजी फिर फर्स्ट में
सरकारी स्कूलों के बच्चे लेते हैं प्रवेश पहली में
कोरे कागज से नही सीखा होता
उन्होंने अभी कुछ भी
आते हैं एक झोला लेकर
मीठी मुस्कान लिए
एक पाटी और बरता रखती है
माँ उसके झोले में
मिलता है उसे दूध और भोजन स्कूल में
वो खुद ही करके सीखता है
अपनी कक्षा की सफाई करना, दरी बिछाना,
अपना दूध का गिलास धोना,
भोजन की थाली धोना
सीखता है लाइन में लगकर खड़े होना
प्राइवेट स्कूल की तरह नही होते है,
पिओन सरकारी स्कूलों में
जो रखते हैं स्कूल साफ
बच्चों के स्कूल आने से पहले
सरकारी स्कूल के बच्चे
मिलकर करते हैं सफाई
अध्यापक की सहायता से
वो जानते है धरती से प्रेम करना,
पौधे लगाना, क्यारी बनाना,
मिट्टी की सुगंध में रचते है कल्पनाएँ
दौड़कर ले आते है हैंड पंप से पानी
झटपट काट देते है खरपतवार
नंगे पाँव ही आ जाते है स्कूल
या तो उसके पास नही होती हैं चप्पलें
या फिर लगता है उन्हें डर
अपनी चप्पलें खो जाने का
कर लेते है जबानी हिसाब-किताब
नही जाते वो किसी कोचिंग में
स्कूल में अध्यापकों ने जो पढा दिया
बस वही होता है उनके पास
छुट्टी के बाद बिना यूनिफॉर्म उतारे ही
दौड़ पड़ते हैं खेतों में,
अपनी गाय भैसों बकरियों को चराने
नही पढाते उनके माँ-बाप घर में
खुद ही पढकर बनते हैं
सरकारी स्कूलों से पढ़े बच्चे अफसर...

आर.एन.आई. नं.- RAJHIN/2019/77486

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

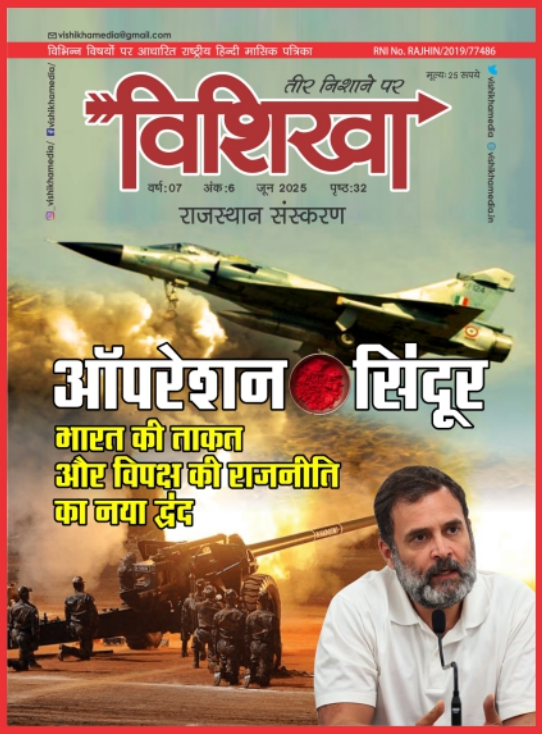

राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद विशिखा

अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित...

विशिखा
तीन निशाने पर...

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contactus:+911413562171,9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia